शहरः विशाखापट्टनम
राज्यः आंध्र प्रदेश

श्रेणीः पोर्ट सिटी, टायर 2

जनसंख्या और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विशाखापट्नम आंध्रप्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यहां एक अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा है, और भारत का पांचवा सबसे व्यस्त बंदरगाह भी। यह एक लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्य भी है। शहर एक औद्योगिक केन्द्र है, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) शामिल है और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे तेजी बढ़ता शहर भी है।

1. डेमोग्राफिक प्रोफाइल

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
कुल जनसंख्या	1728128	14610410	377,106,125
यूए की कुल जनसंख्या (यदि)			
जिला शहरी आबादी में यूएलबी आबादी की हिस्सेदारी (%)	84.88		
जनसंख्या वृद्धि दर (एईजीआर) 2001-11	5.64	2.88	2.76
क्षेत्र (वर्ग मीटर)*	513.61		
जिले में यूएलबी क्षेत्र का हिस्सा (%)*	4.60		
जनसंख्या का घनत्व (व्यक्ति वर्ग प्रति किमी)*	3365		
साक्षरता दर (%)	81.79	79.17	84.11

अनुसूचित जाति (%)	8.49	11.60	12.60
अनुसूचित जनजाति (%)	1.21	2.31	2.77
युवा, 15-24 वर्ष (%)	18.62	19.95	19.68
स्लम जनसंख्या (%)	44.61	7.57	17.36
कार्य आयु समूह, 15-59 वर्ष (%)	67.71	66.06	65.27

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

2. आर्थिक प्रोफाइल

संकेतक	शहर (नगर निगम)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
2004-05 के स्थायी कीमत पर प्रति व्यक्ति आय (रु.)*	50580	33350	रु. 35,947[a]
शहरी गरीबी का अनुपात (शहरी आबादी का %)**	6.35	8.1	13.7
बेरोजगारी दर, 2011-12***	3.95	2.9	3.4
कार्य करने वालों की दर, 2011-12***	36.78	38.2	35.5
कार्य की स्थिति, 2011-12 (प्रतिशत)*** स्व नियोजित: नियमित/मजदूरी वेतनभोगी कर्मचारी: अनौपचारिक श्रम।	 25.77 55.42 18.82	 40.1 40.1 19.8	 42.0 43.4 14.6
मजदूरों का क्षेत्रवार वितरण, 2011-12 (प्रतिशत)*** प्राथमिक द्वितीय तृतीयक	 1.76 33.06 65.18	 8.7 29.8 61.5	 7.5 34.2 58.3
प्रमुख व्यवसायों द्वारा मजदूरों का वर्गीकरण, 2011-12 (प्रतिशत)***			

व्यवस्थापक, वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रबंधक व्यवसाय तकनीशियनों और एसोसिएट पेशेवर क्लर्क सेवा श्रमिक और दुकान एवं मार्केट सेल्स श्रमिक कुशल कृषि एवं मत्स्य श्रमिक शिल्प और संबंधित ट्रेडों के श्रमिक प्लांट और मशीन ऑपरेटरों और संयोजनकर्ता (अस्सेम्ब्लेर्स) एलिमेंटरी व्यवसाय श्रमिक कब्जे से वर्गीकृत नहीं	11.07 6.86 9.72 4.48 17.01 1.70 24.12 10.50 14.54 0	12.7 6.5 7.1 4.5 15.2 4.4 21.6 9.8 18.5 0	15.8 8.8 6.7 5.0 14.7 4.6 19.2 9.2 16.1 0.1
प्राथमिक वस्तु निर्माता#	इस्पात जहाज पेट्रोलियम उत्पाद		
प्रमुख उद्योग##	जहाज निर्माण मिश्रधातु के पहिए खाद्य प्रसंस्करण रसायन		
स्वीकृत एसईजेड की संख्या	11	35	413

नोटः 2007-08, 2008-09 और 2009-10 का 3 वर्ष औसत

स्रोतः *सभी भारत- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय

**राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की यूनिट लेबल डाटा, भारत में घरेलू उपभोक्ता व्यय, 68वां राउंड, 2011-12

*** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की इकाई स्तर डेटा, भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति, 68वां राउंड, 2011-12

#जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

##जिला औद्योगिक प्रोफाइल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, भारत सरकार

3. अवसंरचना स्थिति

संकेतक	शहर (सम्प्रदाय)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
घर के अंदर नल के पानी का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत (बनाये गए स्रोतों से)	71.18	71.52	84.14
बिजली के उपयोग के साथ घरों का %	96.86	97.29	92.68
घर के अंदर शौचालय की सुविधा वाले परिवारों का %	83.58	79.44	72.57
गंदे पानी के माध्यमों का ड्रेनेज से जुड़े परिवारों का प्रतिशत	92.29	85.38	81.77
सीवरेज प्रणाली का प्रकार*	भूमिगत सीवरेज प्रणाली		
ठोस अपशिष्ट प्रणाली का प्रकार*	द्वार से द्वार		
कम्प्यूटर/लैपटॉप का इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत कम्प्यूटर/लैपटॉप का बिना इंटरनेट के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत	8.93 11.39	4.25 7.81	8.27 10.40
मोबाइल फोन के उपयोग के साथ घरों का %	66.90	62.68	64.33
आवास का स्वामित्व पैटर्न (%) स्वामित्व किराए पर	 50.69 47.31	 53.15 45.05	 69.16 27.55
भीड़भाड़ वाले घरों में रहने वाले परिवारों का %	32.54	36.34	32.94
संकेतक	**शहर (डिनोमिनेशन)**		
प्रति 1,00,000 लोगों पर अस्पतालों की संख्या*	3		

प्रति 1,00,000 लोगों पर स्कूलों की संख्या*	
प्राथमिक	8
माध्यमिक	7
द्वितीयक	12
महाविद्यालय	2

स्रोतः मकान, घरेलू सुविधाएं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

*जिला जनगणना पुस्तिका, भारत की जनगणना, 2011

4. राजनीतिक प्रोफाइलः नेतृत्व और प्रशासनिक ढांचा

शासन वास्तुकला *चुने गए एवं कार्यकारी निकायों की संरचना। पदानुक्रम के संकेत दें।*	विशाखापट्नम, जिसे लोकप्रिय तौर पर विजाग के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी भारत में स्थित एक बहुमुखी शहर है। इसका ग्रेटर विशाखापट्नम महानगर पालिका (जीवीएमसी) नामक एक नगरीय निकाय है जिसमें 72 म्युनिसिपल वार्ड हैं। जीवीएमसी एक आयुक्त के नेतृत्व में कार्य करता है तथा विभिन्न उपशीर्षों में संगठित तौर पर विभाजित है। पूर्ववर्ती विशाखापट्नम नगर निगम के क्षेत्रों को गजुवाका नगरपालिका तथा 32 ग्रामों (कुछ नए पंचायत) के साथ मिलाकर अब ग्रेटर विशाखापट्नम महानगर पालिका (जीवीएमसी) के अंतर्गत अभिशासित किया गया है। ग्रेटर विशाखापट्नम महानगरपालिका द्वारा शहर की 20.35 लाख आबादी को पेयजल सुलभ कराया जा रहा है और यह एसपीवी वीआईएसडब्ल्यूसीओ (विशेष प्रयोजन वाहन, विशाखापट्नम औद्योगिक जल आपूर्ति कंपनी) की जरूरतों की पूर्ति भी की जा रही है। जीवीएमसी ने सात जल आपूर्ति परियोजनाओं को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत हाथ में लिया है, जिनमें से इसने चार परियोजनाओं को विलय किए गए पंचायतों, गजुवाका क्षेत्र तथा मध्य व पुराने विशाखापट्नम शहर में विद्यमान जल आपूर्ति प्रणाली के लिए पूर्ण कर लिया है। कई जारी एवं प्रस्तावित परियोजनाओं में येलुरु नहर परियोजना, राईवाडा नहर (पाइप लाइन), अनाकपल्ले जल आपूर्ति सुधार एवं समुद्र-सफाई (डीसैलिनेशन) संयंत्र इत्यादि हैं। निजी संचालकों को सम्मिलित करते हुए निगम द्वारा निर्धारित गड्डो में ही विद्यमान अपशिष्ट

	का वैज्ञानिक तौर पर निबटान किया जाता है। यह स्थल पर ही कचरों का पृथक्करण करता है तथा शत-प्रतिशत हर दरवाजे से कचरों को एकत्र करता है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत जोन-वार अपशिष्ट स्थानांतरण स्टेशन, जल आपूर्ति, सीवरेज तथा शहरी परिवहन पर 8 शहरी अधोसंरचना एवं अभिशासन (यूआईजी) परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। बीओओटी पर 94 जंक्शनों हेतु स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स तथा निगरानी सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। जीवीएमसी, विशाखापट्नम शहरी विकास प्राधिकरण (वीयूडीए) के नियोजन निकाय का भी एक हिस्सा है। वीयूडीए शहर के विकास हेतु मास्टर प्लान तथा जोनल विकास योजनाओं को तैयार करता है। आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीईपीडीसीएल), ग्रेटर विशाखापट्टनम को एक राज्य स्तरीय निकाय बिजली वितरित करता है। आंध्र प्रदेश गृह निर्माण मंडल (एपीएचबी), जिसका गठन दोनों शहरों के तत्कालीन शहर सुधार बोर्ड तथा तत्कालीन नगर सुधार न्यास का एक साथ विलय करके किया गया था, को जीसीएमसी में समेकित/समग्र आवास योजनाओं, दुकानों के निर्माण, व्यावसायिक परिसर तथा बहुमंजिला भवनों की श्रेणी के अधीन आवास के निर्माण में संलग्न किया गया है। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एपीपीसीबी) एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर पर्यावरणीय कानूनों व नियमों के कार्यान्वयन के कार्यों को सौंपा गया है। बोर्ड हैदराबाद स्थित अपने मुख्यालय के माध्यम से कार्य करता हैं और इसका एक आंचलिक कार्यालय विशाखापट्नम में स्थित है।
निर्वाचित प्रतिनिधियों की सं.	लागू नहीं
<u>निर्वाचन विवरण*</u> *चुनाव चक्र, पिछला चुनाव, नाम, जहां प्रासंगिक हो पार्टी की संबद्धता, मुख्य मंत्री, आयुक्त एवं महापौर के लिए कार्यालय ग्रहण करने की तारीख।*	आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तेलुगू देशम पार्टी से श्री चन्द्र बाबू नायडू हैं। उन्होंने 8/6/2014 को निर्वाचित किया गया था। आयुक्त श्री प्रवीण कुमार है।

स्रोतः *संबंधित यूएलबी वेबसाइट और मीडिया सर्च

5. शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) का प्रदर्शन

ऋण और कर

शहरी स्थानीय निकाय की क्रेडिट रेटिंग (नवम्बर 2012 के अनुसार)*	क
संपत्ति कर#	कवरेज (%): 85% से ऊपर संग्रह क्षमता (%): 90% से ऊपर राशि (रु.):

स्रोतः *www.jnnurm.nic.in

#रिफॉर्म मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

यूएलबी में ई-गवर्नेंस और कम्प्यूटरीकरण

सुधार	**स्थिति (कार्यान्वित, प्रगति में और किसी भी टिप्पणी में)**
संपत्ति कर*	कार्यान्वित
लेखांकन*	कार्यान्वित
जल आपूर्ति और अन्य सुविधाएं*	कार्यान्वित
जन्म और मृत्यु पंजीकरण और स्वास्थ्य कार्यक्रम*	कार्यान्वित
नागरिक शिकायत निगरानी*	कार्यान्वित
कार्मिक प्रबंधन प्रणाली*	कार्यान्वित
निर्माण योजना अनुमोदन*	कार्यान्वित
ई-प्रापण*	कार्यान्वित
क्या नागरिक अपने बिल एवं करों का भुगतान सिटिजन फैसिलिटी सेन्टर (सीएफसी) पर कर सकते हैं?#	केवल सीएफसी पर
क्या शहरी स्थानीय निकायों पर भुगतान करने की ऑनलाइन सुविधा है#	हाँ
शहरी स्थानीय निकायों में उपयोग किया जाने वाला ई-मेल सॉफ्टवेयर क्या	एनआईसी

है#	
क्या शहरी स्थानीय निकाय के कार्यालय लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन)/वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं#	हाँ
क्या आप स्टेट डाटा सेन्टर (एसडीसी) का उपयोग करते है?#	नहीं
क्या शहरी स्थानीय निकाय की स्वयं की वेबसाइट है#	हाँ
74वें सीएए का कार्यान्वयन#	सभी 18 कार्यों को जीवीएमसी से हस्तांतरित कर दिया गया है

नोटः यूएलबी में ई-गवर्नेंस के मॉड्यूल कार्यान्वित

स्रोतः *सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट, जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं संबंधित शहरी स्थानीय निकायों की वेबसाइट

#शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

मान्यता

राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के सम्मानों, पुरस्कारों, पायलटों, क्षैतिज नेटवर्कों की सूची।	• आईसीएलईआई के सदस्य • भारत के शीर्ष 20 उदीयमान शहरों में स्मार्ट सिटी काउंसिल • नगर रत्न 2011 (शासन में आईटी का उपयोग)

6. वित्तीय एवं स्वास्थ्य

वित्तीय

संकेतक	सिटी (सम्प्रदाय)	राज्य (शहरी)	भारत (शहरी)
बैंकिंग सुविधाओं के उपयोग के साथ घरों का %	64.01	57.21	67.77

वित्तीय स्थिति*		
नगर निगम के आय और व्यय का विवरण	आय	व्यय
2009-10	लागू नहीं	लागू नहीं
2010-11	लागू नहीं	लागू नहीं

2011-12	131899.27[+]	129990.00[+]
नगरीय गरीबों के लिए आरक्षित बजट का प्रतिशत@	25%	

स्रोतः मकान, घरेलू सुविधाएं और परिसंपत्तियों की तालिका, भारत की जनगणना, 2011

#शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की 2012 की सूचना एवं सेवाएँ आवश्यकता आकलन (आईएसएनए) अध्ययन

[@] जेएनएनयूआरएम, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट

[+] वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आंकड़े

पर्यावरण

स्वच्छ भारत रैंकिंग*	205
उपलब्ध शहरों के लिए व्यापक पर्यावरण आकलन#	70.82

स्रोतः *प्रेस सूचना ब्यूरो, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2015

#केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, 2009

7. क्षमताः ट्रैक रिकार्ड और पहल

जेएनएनयूआरएम परियोजनाएं	स्थिति या टिप्पणी			
बीएसयूपी/आईएचएसडीपी	बीएसयूपी योजना के अंतर्गत, कुल 12 परियोजनाओं (5 अधोसंरचना और 7 आवास निर्माण) को मंजूर किया गया था, जिसमें से 5 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। कुल परियोजना लागत रु. 764.22 करोड़ थी। आवास परियोजनाओं का हिस्सा 70% (रु. 538.11 करोड़) तथा अधोसंरचना परियोजना का हिस्सा 30% (रु. 226.11 करोड़) है। अधोसंरचना की सभी 5 परियोजना को पूर्ण कर लिया गया है जबकि आवास परियोजनाएं प्रगति पर हैं। आवास की 95% इकाइयों के निर्माण को पूर्ण कर लिया गया है।			
यूआईजी/यूआईडीएसएसएमटी	यूआईजीः कुल 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। 8 परियोजनाओं को पूरा कर दिया गया है और 6 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर हैं।			
परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत (लाख रु. में)	154677.48			
परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	कुल लागत (लाख रु.	कुल स्वीकृत

			में)	परियोजनाओं में क्षेत्र की हिस्सेदारी
	जल	10	74128.48	47.9
	जल निकासी/ एसडब्ल्यूडी	1	7227	4.7
	सीवरेज	2	28152	18.2
	परिवहन	1	45170	29.2
केन्द्र द्वारा जारी सहायता का हिस्सा (प्रतिशत)	88.62			
पूरा किए हुए कार्य का प्रतिशत (वास्तविक प्रगति)	69			
निधि उपयोगिता (%)	79.5			
शहरी विकास मंत्रालय की योजनाओं के साथ एकत्रीकरण	स्थिति, टिप्पणी			
विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना (हृदय)				
अमृत				
जेएनएनयूआरएम	*शहर अमृत मिशन के तहत शामिल है। राज्य वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत की जा चुकी है।*			
एनयूआईएस	*शहर जेएनएनयूआरएम के घटक तहत कवर था।*			
एनयूआईएस				
पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)				

स्रोतः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार